
PROCEDURE TO BE FOLLOWED BY THIS OFFICE FOR PROCESSING OF PENSION CASES

1. On receipt of pension papers complete in all respects from the Head of Office six months in advance from the date of superannuation of Government employee, the Accountant General (A&E) - II, Madhya Pradesh shall apply requisite checks for determining the admissibility of pension and gratuity and also family pension cases.
2. If any information/clarification is wanted, the Head of Office shall be contacted within 3 months from the date of receipt of pension papers.
3. Where no information/clarification is desired or where necessary clarification has been received from the Head of Office, the Accountant General (A&E) - II, Madhya Pradesh shall straightway issue (i) Pension Payment Order, (ii) authority for payment of gratuity and (iii) authority for payment of commuted value of pension one month in advance from the date of superannuation of the Government employee.
4. This Office shall send pensioner's copy of intimation letter regarding issue of Pension Payment Order and the authority for payment of retiring gratuity and commuted value of pension to the concerned Head of Office under whom the retiring employee is serving and the both halves of Pension Payment Order to the Pension Disbursing Officer, as chosen by the retiring Government employees, with the direction to start payment from the specific date as fixed therein.
5. When the retiring employees is in receipt of higher pay on the basis of interim orders passed by the Hon'ble High Court, Hon'ble Supreme Court of India, Madhya Pradesh Administrative Tribunal or where appeal, if any, preferred by the Government is pending, such higher pay may be taken into account for calculation of pension only on provisional basis till finalization of the case. No gratuity or commuted value of pension shall be authorized in such cases till finalization of the court case and issue of consequential Government instructions.
6. Where payment of pension/family pension is to be made in other State, the Special Seal Authority for payment of pensionary benefits may be issued as usual to the concerned Accountant General, in whose audit jurisdiction the pensioner intends to draw pension.

पेंशन मामलों के प्रसंस्करण के लिए इस कार्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

1. सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले कार्यालय प्रमुख से सभी तरह से पूर्ण पेंशन के कागजात प्राप्त होने पर, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, ग्वालियर मध्य प्रदेश पेंशन की स्वीकार्यता, ग्रेच्युटी और पारिवारिक पेंशन के मामले भी निर्धारित करने के लिए अपेक्षित चेक लागू करेगा।
2. यदि कोई सूचना / स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो कार्यालय प्रमुख से पेंशन कागजात प्राप्त होने की तारीख से 3 महीने के भीतर संपर्क किया जाएगा।
3. जहां कोई सूचना / स्पष्टीकरण वांछित नहीं है या कार्यालय प्रमुख से आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, ग्वालियर मध्य प्रदेश पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा (i) पेंशन भुगतान का अधिकार और (ii) ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए प्राधिकरण और (iii) सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के भुगतान के लिए प्राधिकरण।
4. यह कार्यालय पेंशन भुगतान आदेश, रिटायरिंग ग्रेच्युटी और पेंशन के कम्यूटेड मूल्य के भुगतान के अधिकार के संबंध में पेंशनर की सूचना पत्र की प्रतिलिपि संबंधित कार्यालय के प्रमुख को भेजेगा जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी सेवारत है, और निश्चित तिथि से भुगतान शुरू करने की दिशा में, पेंशन भुगतान के दोनों हिस्सों सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों द्वारा चुना गया पेंशन वितरण अधिकारी को भेजा जाएगा।
5. जब सेवानिवृत्त कर्मचारी माननीय उच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण या जहां सरकार द्वारा पसंदीदा अपील, यदि कोई हो, लंबित है, ऐसे उच्चतर वेतन को मामले के अंतिम रूप तक अनंतिम आधार पर पेंशन की गणना के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। पेंशन का कोई ग्रेच्युटी या कमिटेड वैल्यू ऐसे मामलों में अधिकृत नहीं होगा, जब तक कि कोर्ट केस फाइनल नहीं कर देता और परिणामी सरकारी निर्देश जारी नहीं कर देता।
6. जहां पेंशन / पारिवारिक पेंशन का भुगतान अन्य राज्य में किया जाना है, पेंशन लाभ के भुगतान के लिए विशेष सील प्राधिकरण सामान्य रूप से संबंधित महालेखाकार को जारी किया जा सकता है, जिसके ऑडिट क्षेत्राधिकार में पेंशनर, पेंशन आकर्षित करने का इरादा रखता है।